बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 213 ● नई दिल्ली ● सोमवार 25 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मिजोरम तक पहुंची भारतीय रेल, 13 सितंबर को पीएम मोदी वहां के पहले रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली । मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नक्शे से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात देने जाते हैं। अगले महीने 13 सितंबर को बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। यह ऐतिहासिक तोहफा आइजोल को मिलेगा। बैराबी-सैरांग रेल लाइन के उद्घाटन को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 सितंबर को आइजोल आएंगे और रात वहीं गुजारेंगे। इसके बाद 13 सितंबर को नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस दौरे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत कर ली है।

दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन, लोकतंत्र को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का भव्य आयोजन रविवार को आरम्भ किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया, जहां लोकतंत्र को मजबूत करने और विधायी प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा की गई। दरअसल, यह आयोजन राज्यों के बीच सहयोग और अनुभव साझा करने का अनूठा मंच है। आशा है कि यहां सभी को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा लेंगे।

पिछले 6 माह में ही दिल्ली में कई काम हुए

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम के आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज से 100 साल पहले 24 अगस्त 1925 को 11 बजे इसी भवन में सदन लगा था, जिसमें विठ्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके पश्चात सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह के साथ-साथ आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और कहा कि पिछले 6 माह में ही दिल्ली में इतने नए-नए काम हुए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। सीएम ने कहा कि ब्रिटिश सरकार में कड़े मुकाबले में चुनाव जीत कर कोई उनकी संसद का अध्यक्ष बना तो वे विट्ठल भाई पटेल थे। इस पद पर रहते हुए उनका कार्यकाल अंग्रेजों से सदैव टकरावपूर्ण रहा।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि यह अखिल भारतीय सम्मेलन भारतीय लोकतंत्र की शक्ति एवं संजीविता का उत्सव है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद विधानसभाएं एवं विधान परिषदें भारत की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही हमारी पहचान है। आप सभी इन निर्वाचित अधिकारी होने के नाते हमारे लोकतंत्र संरचना को बेहतर बनाने की बड़ी जिम्मेदारी का निर्माण करते हैं। हमारे विधानसभा और विधान परिषद 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं अभिलाषाओं का निर्माण करती है।

कुछ ठोस सुझाव निकलेंगे

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजजू ने कहा कि यह महत्वपूर्ण स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से आप लोगों के बीच में विचार विमर्श करके सही रिकमेंडेशंस आगे आएंगी। कहा कि यह कहना मुश्किल है कौन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कैसे बेहतर सदन चलाते हैं। सभी के कुछ थोड़ा बहुत नियम में बदलाव है। कई देश और विदेश के लोग मुझसे पूछते हैं कि संसद में बहुत हंगामा होता है तो मैं कहता हूं कि यहां हंगामा नहीं होता तो कहां होगा, मगर मेरा मानना है कि सदन में काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। कहा कि उम्मीद है कि इस सम्मेलन से कुछ ठोस सुझाव निकलेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

यह रहे उपस्थित

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा और डॉ. पंकज सिंह समारोह में उपस्थित रहे। आयोजक और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उत्साहपूर्वक पहुंचे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आगमन की प्रतीक्षा में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता, प्रवेश वर्मा और उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने विधानसभा परिसर में स्वागत की तैयारियां की।

हनुमान जी का भक्त आसमान की ऊंचाइयों को छूकर लौटा है, शुभांशु शुक्ला के लिए बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली ।

दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और गगनयान मिशन पर जाने वाले उनके अन्य सहयोगियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने गगनयात्रियों की जमकर तारीफ की और कहा कि पूरे देश को गगनयात्रियों पर गर्व है और सभी देशवासी गौरवान्वित हैं।

देशवासियों को गगनयात्रियों पर गर्व

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आप सभी ने जो मेहनत की, वह न केवल प्रभावशाली थी, बल्कि मैं कहूंगा कि उत्कृष्ट थी। मुझे भारत माता के सपूत, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य सहयोगियों, ग्रुप कैप्टन पी वी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सचमुच गर्व महसूस हो रहा है। सभी देशवासियों को आप सभी पर गर्व है। आप सभी ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है। सुब्रतो पार्क में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गगनयान मिशन आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतीक है। फरवरी 2024 में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र

(वीएसएससी) के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पहली बार शुभांशु शुक्ला समेत अन्य गगनयात्रियों के नामों का खुलासा किया था। गगनयान मिशन का उद्देश्य 2027 में तीन दिवसीय मिशन के लिए तीन सदस्यीय चालक दल को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित पृथ्वी की कक्षा में भेजना है।

चंद्रमा से लेकर मंगल तक भारत की उपस्थिति

राजनाथ सिंह ने कहा, हमारा योगदान केवल अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने तक ही सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे अभियानों के लिए भी पूरी तरह तैयार है। मैं इसे केवल एक तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के एक नए अध्याय के रूप में देखता हूं, जहां हम दुनिया की प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों के बीच पूरे गौरव के साथ खड़े हैं।

अंतरिक्ष हमारे लिए सिर्फ अनुसंधान का विषय नहीं

रक्षा मंत्री ने कहा, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम केवल प्रयोगशालाओं और प्रक्षेपण यानों तक ही सीमित नहीं है। यह हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक दृष्टि का प्रतीक है। भारत अंतरिक्ष को केवल अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि हम इसे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, ऊर्जा और मानवता के भविष्य के रूप में देखते हैं। आने वाले समय में, अंतरिक्ष खनन, रिसर्च और ग्रहों से मिलने वाले संसाधन मानव जाति की दिशा बदल देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मैं लखनऊ संसदीय क्षेत्र से आता हूं, शुभांशु शुक्ला वहीं से हैं। वह हमारे मतदाता भी हैं।

शुभांशु शुक्ला बजरंग बली के भक्त

राजनाथ सिंह ने शुभांशु शुक्ला के बारे में आगे कहा कि मुझे यह भी बताया गया कि आप (शुभांशु शुक्ला) भी बजरंग बली के भक्त हैं। और आपने वहां (अंतरिक्ष में) कई बार हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। आज हनुमान जी का एक भक्त आसमान की ऊंचाइयों को छूकर लौटा है और हम सबके बीच मौजूद है। मेरा मानना है कि यह सिर्फ विज्ञान की जीत नहीं है। यह हमारे विश्वास की भी जीत है। जब शुभांशु अंतरिक्ष में गए, तो वे सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के, सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि बनकर गए। नागरिक क्षेत्र में आपका योगदान इतिहास में दर्ज होगा।

मुझे बताया गया कि शुभांशु ने अंतरिक्ष में खेती भी की है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत का कोई किसान अंतरिक्ष में जाकर मेथी और मूंग की खेती करेगा। निश्चित रूप से, आपका अनुभव हमारे आगामी अभियानों में बहुत मददगार साबित होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां अंतरिक्ष अब केवल सैन्य शक्ति या तकनीकी कौशल का प्रतीक नहीं रह गया है। यह मानव सभ्यता की यात्रा में एक नया मील का पत्थर है। भारत ने हमेशा दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया है। आज हमारे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष में हमारे अंतरिक्ष यात्री उस संदेश को नई ऊँचाइयों पर ले जा रहे हैं।

कालिंदी कुंज में रास्ता देने को लेकर हुआ विवाद, बहन के सामने लड़कों ने युवक को पीटा

नई दिल्ली ।

दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में शनिवार की रात रोडरेज का मामला सामने आया है. इस मामले में कुछ लड़कों ने एक युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी. युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी लड़कों का उसकी बहन के साथ बहसबाजी का विरोध किया था. बस यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी और उन्होंने गुस्से में आकर पीड़ित युवक सोमित (18) की बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं गुस्साए आरोपी इतने हिंसक हो चुके थे कि उन्होंने पास में पड़ा एक गमला उठा कर उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 अगस्त की रात करीब 10:26 बजे मदनपुर खादर से पुलिस कंट्रोल रूम को लगातार दो कॉल्स मिलीं. पहली कॉल में कहा गया कि कुछ लड़कों ने चाकू से हमला किया है, वहीं दूसरी कॉल में आरोप था कि बहन से छेड़छाड़ के बाद झगड़ा हुआ. अधिकारियों ने बताया कि कॉल्स की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और पीसीआर वैन तुरंत मौके पर पहुंची. जहां पुलिस ने पाया कि मदनपुर खादर के जेजे कॉलोनी के रहने वाला 18 वर्षीय सोमित बुरी तरह घायल पड़ा था. उसे तुरंत पीसीआर वैन की मदद से एलबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि सोमित अपनी बहन के साथ बाजार से घर लौट रहा था. गली में कुछ लड़के खड़े थे, जिन्हें उसकी बहन ने रास्ता देने को कहा. लेकिन, आरोपी वहां से हटने की बजाय उससे बहसबाजी करने लगे, जिसका सोमित ने विरोध किया. बात इतनी बढ़ गई कि लड़कों ने मिलकर सोमित पर हमला कर दिया. पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, जिसमें न तो चाकू चलाने की बात पाई गई और न ही बहन से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई. पूरा मामला सिर्फ रास्ता रोकने और बहस से उपजा झगड़े का परिणाम था. इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. वहीं, पीड़ित का आरोप कि चारों लड़के उसकी बहन को छेड़ने रहे थे, उसने विरोध किया तो उनलोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया. स्थानीय लोगों की मानें तो पीड़ित को आसपास मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और पुलिस मामले में ठोस कार्रवाई करने से बच रही है.

आर्द्रभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को दो महीने के भीतर सीमा तय करने का दिया आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में आर्द्रभूमियों की सीमा तय करने और उसकी जमीनी हकीकत की प्रक्रिया पर गंभीर नाराजगी जताई है। अदालत ने साफ कहा कि राज्य आर्द्रभूमियों प्राधिकरण कछुए की चाल से काम कर रहे हैं। इसलिए सभी राज्यों को आदेश दिया गया है कि दो महीने के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की सीमा चिन्हित कर इसे सार्वजनिक करें। अदालत ने यह भी कहा कि यदि निर्देश का पालन नहीं हुआ तो संबंधित राज्यों के पर्यावरण विभाग के सचिवों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि अब तक राज्यों द्वारा की गई कवायद बेहद निराशाजनक रही है। कोर्ट ने कहा कि पहले भी दिशा-निर्देश दिए गए थे, लेकिन नतीजे सकारात्मक नहीं निकले। अदालत ने साफ चेतावनी दी कि अगर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने इस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो कोर्ट मजबूरन कठोर आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आर्द्रभूमि की पहचान की जा चुकी है, इसलिए अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे इन्हें अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करें। अदालत ने आदेश दिया कि यह काम तुरंत पूरा किया जाए और अनुपालन का शपथपत्र दायर किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि अगली सुनवाई से पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। कोर्ट ने 19 अगस्त को दिए अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को भी राज्यों के आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा और लंबित अधिसूचनाओं को जल्द जारी करना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि आंकड़ों के अनुसार 2.25 हेक्टेयर से छोटी आर्द्रभूमि की संख्या लगभग 5,55,557 है और इन्हें भी मौजूदा नियमों के अनुसार चिन्हित करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि राज्यों द्वारा दाखिल किए जाने वाले शपथपत्रों में यह भी बताया जाना चाहिए कि इन छोटी आर्द्रभूमि की रक्षा के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। अदालत ने यह मामला 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

याचिका और हस्तक्षेपकर्ता

यह मामला पक्षी प्रेमी आनंद आर्य, अधिवक्ता एम.के. बालाकृष्णन और एनजीओ वनशक्ति द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर चल रहा है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से कहा कि इसरो ने पहले ही 2,31,195 आर्द्रभूमि (2.25 हेक्टेयर से बड़े) की पहचान कर ली है, जबकि छोटे आर्द्रभूमि की संख्या 5,55,557 है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इन सभी आर्द्रभूमि को सुरक्षित करने की दिशा में जल्द और ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह पर्यावरण और जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम, पुलिस ने नवीन बाली गैंग के तीन शूटर को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस ने नवीन बाली गैंग के तीन कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद मिले हैं. पुलिस का कहना है गिरफ्तार किए गए शूटर दिल्ली में बड़ी गैंगवार की साजिश रच रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है. पुलिस 15 अगस्त के मद्देनजर हाई अलर्ट होने के कारण पूरे इलाके में चेकिंग और एरिया डॉमिनेशन ड्राइव चलाई. इसी दौरान पुलिस टीम ने बावना में एक संदिग्ध बाइक को ओयो होटल के बाहर खड़ी देखी. बाइक लंबे समय से वहीं खड़ी थी. पुलिस को शक होने पर होटल प्रबंधन से पूछताछ की तो पता चला कि बाइक का मालिक तीन दिनों से होटल में ठहरा है. जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो तीन युवक संदिग्ध हालत में मिले. तलाशी के दौरान उनके पास से पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा और तीन कारतूस बरामद हुए. जांच में सामने आया कि मामला दो कुख्यात गैंग राजेश बावानिया गैंग और नवीन बाली गैंग की पुरानी दुश्मनी से जुड़ा है. साल 2023 में कंझावला इलाके में अजय उर्फ बहादुर की हत्या हुई थी. इस वारदात का मुख्य आरोपी अनिकेत, राजेश बावानिया का दामाद था. वहीं 2025 में बवाना इलाके में धर्मवीर उर्फ बिल्लू की हत्या कर दी गई. बिल्लू नवीन बाली गैंग से जुड़ा हुआ था. पुलिस का कहना है कि इन हत्याओं का बदला लेने के लिए नवीन बाली ने जेल के अंदर से ही नई साजिश रची. उसने अपने शूटरों को टारगेट तय करने और हत्या की तैयारी करने के निर्देश दिए. पुलिस ने जिन कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान अंजर आलम, रितिक, राजेश कुमार उर्फ सरदार के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी 11 अगस्त से ओयो होटल, बवाना में ठहरे हुए थे और

लगातार रेकी कर रहे थे. जांच में आरोपियों ने बताया कि रितिक को टारगेट की रेकी का जिम्मा सौंपा गया था. अंजर और राजेश को हत्या को अंजाम देना था. वहीं विदेश में छिपा गैंग लीडर हिमांशु भाऊ लगातार अंजर से संपर्क में था. उसने वारदात के लिए सत्तर हजार रुपए भी भेजे थे. तीनों आरोपी आपस में व्हाट्सऐप कॉल और चैट के जरिए संपर्क में रहते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से और अंजर आलम के खुलासे पर छापेमारी करके कुल मिलाकर, दो पिस्टल, दो मैगजीन, 27 जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा, तीन मोबाइल फोन, जिनमें गैंगवार की बातचीत दर्ज है, को बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ बवाना पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जेल से साजिश कैसे रची गई और विदेश में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का नेटवर्क किन-किन जगहों पर फैला हुआ है.

भारत की नीली अर्थव्यवस्था- मानसून सत्र में बने पांच नए समुद्री कानून समुद्री क्रांति है, जो विज़न 2047 आत्मनिर्भर भारत में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगे

भारत को प्राचीन काल में ही समुद्री सभ्यता और व्यापारिक शक्ति के रूप में जाना जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल बंदरगाह से लेकर चोल साम्राज्य की दक्षिण-पूर्व एशिया तक विस्तृत समुद्री कूटनीति, भारत ने हमेशा सागर को अपनी समृद्धि और शक्ति का आधार बनाया है।लेकिन औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक समुद्री क्षेत्र में व्यापक सुधार नहीं हो पाए।वर्तमान में वैश्विक व्यापार का लगभग 80 पेर्सेंट वॉल्यूम और 70 पेर्सेंट वैल्यू समुद्री मार्ग से होती है। भारत की तटीय लंबाई 7,517 किमी है,200 से अधिक बंदरगाह और विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन है।मैं एडवोकेट किशन सम्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र मानता हूं कि फिर भी भारत का योगदान वैश्विक शिपिंग में सीमित रहा।इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने 2025 में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक साथ पांच बड़े समुद्री विधेयक लाकर संसद के दोनोंसदनों में पारित कर कानून बनाकर एक समग्र समुद्री सुधार पैकेज प्रस्तुत किए जो, सिर्फ विधायी सुधार नहीं, बल्कि भारत की समुद्री क्रांति है। ये कानून न केवल व्यापार दक्षता बढ़ाएंगे,बल्कि भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाएंगे। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज मिलेगा,बल्कि नीली अर्थव्यवस्था के सतत विकास औरआत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह कदम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए, आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे। साथियों बात अगर हम संसद के मानसून सत्र 2025 के दोनों सदनों में पारित होकर कानून बने इन पांचों समुद्री कानूनों को जानने की करें तो,(1) बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक, 2025- बिल्स ऑफ लैडिंग समुद्री व्यापारका सबसे अहम दस्तावेज होता है,जो माल लदाई का प्रमाण, स्वामित्व का सबूत और व्यापारिक अनुबंध का हिस्सा होता है। नए विधेयक का उद्देश्य इसे डिजिटल और ब्लॉकचेन- आधारित प्रणाली से जोड़ना है ताकि नकली दस्तावेज, धोखाधड़ी और पारदर्शिता की कमी को दूर किया जा सके। इसका प्रभाव यह होगा कि निर्यातक और आयातक दोनों को सुरक्षित और तेज़ लेन-देन की सुविधा मिलेगी। (2) समुद्री माल ढुलाई विधेयक,2025-यह विधेयक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत में माल ढुलाई अनुबंधों को विनियमित करेगा। अब जहाज कंपनियों, निर्यातकों और आयातकों के बीच विवाद समाधान तेज होगा। बीमा, देरी और हर्जाने के मामलों में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं।इससे भारत का ईज़ऑफ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग बेहतर होगी।(3) व्यापारिक पोत परिवहन विधेयक,2025-यह कानून भारतीय जहाज़ी बेड़े के आधुनिकीकरण और नए पोतों में निवेश को बढ़ावा देगा। विदेशी जहाज़ कंपनियों के मुकाबले भारतीय कंपनियों को प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलेगा।साथ ही, पोतपुनर्निर्माण (शिपबिल्डिंग) इंडस्ट्री और रोजगार में उछाल आएगा।(4) तटीय नौवहन विधेयक,2025- तटीय नौवहन कानून पोर्ट्स व्यापार और यात्री सेवाओं को नई दिशा देगा। यह एक देश-एक परमिट• की अवधारणा लाता है, जिसके तहत जहाज़ आसानी से भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर बिना जटिल प्रक्रियाओं के संचालन कर सकेंगे।इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी और माल परिवहन तेज़ होगा।(5) भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 -यह कानूनभारतीय बंदरगाहों को स्वायत्त, तकनीकी रूप से उन्नत और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने पर केंद्रित है। इसमें ग्रीन पोर्ट्स, स्मार्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना है। इसका सीधा प्रभाव भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी और निर्यात प्रतिस्पर्धा पर पड़ेगा। साथियों बात अगर हम इन पांचो कानून के परफॉर्मेंस को प्वाइंट में समझकर करें व एक साथ ही पेश पारिकरने को समझने की करें तो,(1)भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज-जीडीपी योगदान 2030 तक भारत की ब्लू इकोनॉमी जीडीपी का 12पेर्सेंट तक योगदान कर सकती है,जो वर्तमान में 4 पेर्सेंट है।(2) लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी 13-14 पेर्सेंट से घटकर 8-9 पेर्सेंट तक। (3) रोजगार सृजन शिपबिल्डिंग और पोर्ट लॉजिस्टिक्स में 20 लाख से अधिक नए अवसर। (4)निर्यात प्रतिस्पर्धा- तेज़ डिलीवरी और कम लागत से भारत डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच प्रतिस्पर्धा में मजबूत होगा। (5) नीली अर्थव्यवस्था के विकास में तेज़ भूमिका-नीली अर्थव्यवस्था सिर्फ शिपिंग तक सीमित नहीं है।इसमें मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री खनिज, ऑफशोर ऊर्जा, और बायोटेक्नोलॉजी भी शामिल हैं।यूएनसीटीएडी की 2023 रिपोर्ट बताती है कि ब्लू इकोनॉमी से विश्व स्तरपर 3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी जुड़ी हुई है।भारत की,ईईजेड (2.4 मिलियन वर्ग किमी) दुनियां में सबसे बड़ी में से एक है।(6) नए कानून समुद्री ऊर्जा (ऑफशोर विंड्स,वेव एनर्जी), खनिज संसाधन (पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स), और समुद्री बायोटेक्नोलॉजी को कानूनी ढांचा देंगे। (7) व्यापार दक्षता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा- डब्ल्यूटीओ की ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट (टीएफए) में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और तेज़ क्लियरेंस की अनिवार्यता है,जो भारत के नए कानून इससे मेल खाते हैं। (8)आईएमओ के ग्रीन शिपिंग टारगेट्स (2050) के तहत जहाज़ों से कार्बन उत्सर्जन 50 पेर्सेंट घटाने का लक्ष्य है। भारत का व्यापारिक पोत कानून इसी दिशा में ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देगा। (9) चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) समुद्री बंदरगाह नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत इन सुधारों से एशियाई सप्लाई चेन में एक मजबूत विकल्प बनेगा। (10) पांच विधेयक एक साथ क्यों-(i) उद्योग को स्पष्ट संदेश कि भारत सिर्फ टुकड़ों में नहीं, बल्कि समग्र सुधार चाहता है।(ii) डब्ल्यूटीओ और आईएमओ की अंतरराष्ट्रीयप्रतिबद्धताओं को एक साथ पूरा करना। (iii) औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त करने का राजनीतिक और आर्थिक संकल्प।(11) मारिटाइम इंडिया विज़न 2047 का रोडमैप तैयार करना। (11) औपनिवेशिक कानून का अंत और नई शुरुआत-(i)अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून व्यापार को नियंत्रित करने के लिए थे, भारत के हितों के लिए नहीं। (ii) अब नए कानून भारतीय समुद्री स्वायत्तता का प्रतीक हैं। (iii) इससे तटीय समुदायों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा-(i) मछुआरों को आधुनिक कोल्ड-चेन और तेज़ निर्यात सुविधा।(ii) तटीय पर्यटन उद्योग को स्मार्ट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। (iii) स्थानीय युवाओं को लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और मैन्युफैक्चरिंग में रोज़गार। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत की नीली अर्थव्यवस्था- मानसून सत्र में बने पांच नए समुद्री कानून,समुद्री क्रांति है जो विज़न 2047 आत्मनिर्भर भारत में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होंगेपांच नए समुद्री कानून भारत के विज़न आत्मनिर्भर भारत 2047 में विकसित राष्ट्र और वैश्विक समुद्री महाशक्ति बनाने में अहम रोल अदा करेंगे भारत में पांच नए समुद्री कानून भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट डोज देने के साथ, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ब्लू इकोनामी पावर हाउस के रूप में स्थापित करेंगे।

सम्पादकीय...

क्यों बेचैन हैं एनडीए के ओबीसी नेता?

राकांपा नेता शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने हालिया दिनों में कांग्रेस के एक बड़े नेता से मिलकर उन्हें अपनी पार्टी हेडक्वार्टर के लिए आवंटित नई दिल्ली स्थित 81, लोदी एस्टेट निवास रहने के लिए ऑफर किया है, कहते हैं इस नेता ने सुप्रिया के इस 'मुश्किल ऑफर' को आसानी से स्वीकार भी कर लिया है। सनद रहे कि यह नेता पहली बार के सांसद हैं, इस नाते उन्हें रहने को छोटा सरकारी आवास ही आवंटित हुआ है, पर उनके मुलाकातियों की संख्या को देखते हुए उन्हें एक बड़े घर की दरकार थी, सुप्रिया ने मौके की इसी नजाकत को भांपते हुए नेता जी को 81 लोदी एस्टेट का अपनी पार्टी का दफ्तर ही ऑफर कर दिया। दरअसल, शरद पवार पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र की अपनी जमीन को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, वे जब भी उद्धव ठाकरे से बात करते हैं तो शिवसेना प्रमुख उनकी रंग बदलती सियासत को देखते हुए बेसाख्ता कह देते हैं कि 'आपके बारे में कहा जाता है कि आपकी मोदी जी से इतनी गहरी छनती है कि आप महीने में कम से कम दो बार उनसे बात जरूर करते हैं। उन्होंने आपसे यह भी वायदा किया हुआ है कि बिहार चुनाव के बाद वे आपकी पुत्री को अपनी सरकार में शामिल करेंगे।' इसी कड़ी में बड़े पवार ने अपने घर अपने कुछ मुंहलगे पत्रकारों को डिनर पर आमंत्रित किया और उनसे 'ऑफ द रिकार्ड' बात करते हुए उन्होंने कहा-मैं चाहता हूं कि हम विपक्ष में रह कर अब अपनी भूमिका मजबूत करें, आजकल शरद पवार परिवार कांग्रेस के प्रति इतनी आस्था दिखा रहा है। सूत्रों की मानें तो करीब दो सप्ताह पहले केंद्रीय मंत्री व अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल और यूपी की मल्लाह राजनीति के केंद्र रहे संजय निषाद के बीच एक लंबी और सारगर्भित मुलाकात हुई। कहते हैं कि अनुप्रिया ने अपने दर्द को स्वर देते हुए कहा कि 'भाजपा की नजरों में हमारी कोई कद्र नहीं, हमें 6-7 सीटों पर ही निपटा देंगे, चूंकि आपका बेटा भी इस बार चुनाव हार गया है सो, आपका समय तो और भी मुश्किलों भरा है।' संजय निषाद भी चाहते हैं कि यूपी के ये छोटे-छोटे दल इकट्ठे होकर अपना एक 'संयुक्त मंच' बना लें जिससे कि भाजपा नेतृत्व से ठीक से तोलमोल के बोल हो सकें। कहते हैं इसी कड़ी में इन नेताओं ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी से भी बात की। जयंत से कहा गया कि 'हम सभी नेताओं को एक मंच पर आकर एकजुटता में अपनी ताकत दिखानी होगी तभी हम भाजपा नेतृत्व पर कोई दबाव बना पाएंगे।' माना जाता है कि जयंत चौधरी भी इन दिनों भाजपा नेतृत्व से थोड़े खफा-खफा चल रहे हैं क्योंकि भले ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया हो, पर पिछले सालभर में उनके मंत्रालय को कोई फंड ही आवंटित नहीं हुआ है, ऐसे में वे स्वयं को मंत्री 'विदआउट पोर्टफोलियो' जैसा ही महसूस कर रहे हैं। इसके बाद इस नए मंच के गठन के लिए यूपी में पिछड़ों के एक बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर से भी बात की गई है। फिलवक्त इन नेताओं ने मिल कर यही सामूहिक रणनीति बनाई है कि ये नेतागण घूम-घूम कर अपने-अपने क्षेत्रों में रैलियां व जनसंपर्क अभियान करेंगे और भाजपा को यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि 'वह सिर्फ अगड़ी जातियों के दम पर सरकार में नहीं है, उन्हें पिछड़ी जातियों की भी इतनी ही जरूरत है।' अभी दो-तीन दिन पहले ही भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को तलब कर उनकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। दरअसल, चिराग को लेकर बिहार चुनाव में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी खबर आती है कि वे बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, कभी यह कि वे प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ सीटों का तालमेल कर सकते हैं। इस पर भाजपा के एक कद्दावर नेता ने चिराग को तलब कर उनसे दो टूक पूछ लिया-आप अलग-अलग जगह पर अलग-अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा असमंजस बना हुआ है कि आप करेंगे क्या? इस पर चिराग ने कहा कि 'वे एनडीए में रह कर एनडीए के हाथ ही मजबूत करना चाहते हैं, पर भाजपा बताए कि उनके लिए वह कितनी सीटें छोड़ेगी।' कहते हैं इस पर उस बड़े भाजपा नेता ने कहा कि हम सीटों की बात बाद में करेंगे, पहले आप यह बयान जारी करें कि आप एनडीए के अंदर रह कर ही चुनाव लड़ेंगे।' दरअसल इस पूरे कथानक के पीछे भाजपा का अपना एक जनमत सर्वेक्षण है। सूत्र बताते हैं कि अभी पिछले दिनों भाजपा ने बिहार में अपना एक अंदरूनी सर्वेक्षण करवाया है, यह सर्वे 'एसआईआर' और वोट चोरी के हंगामे के बाद के तापमान को नापने के लिए आहूत हुआ था। इस सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि अगर इस दफे के चुनाव में भाजपा अपने दम पर सारी सीटों पर चुनाव लड़ जाए तो वह 70-75 सीटों पर सिमट सकती है, अगर वह लोक जनशक्ति यानी चिराग के साथ लड़ें तो उसे 10 सीटों का इजाफा हो सकता है, पर अगर वह जदयू के साथ चुनाव में गई तो वह जरूरी बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच सकती है। वैसे भी नीतीश ने भाजपा नेतृत्व से दो टूक कह दिया है कि 'चिराग पासवान के साथ रहने या ना रहने से गठबंधन को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, अगर चिराग के लिए भाजपा सीटें छोड़ना चाहती है तो वह अपने कोटे से छोड़े।' महीने भर का वक्त हो गया, पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहीं नजर नहीं आ रहे, वे किसी से मिलने-जुलने से भी गुरेज कर रहे हैं। कहते हैं अभी पिछले सप्ताह पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं का एक जत्था उनसे मिलने उनके आवास पर पहुंचा, उन्हें सम्मान के साथ बिठाया गया, चाय-पानी पिलाई गई और बाद में उन्हें बता दिया कि अभी धनखड़ जी किसी से मिल नहीं रहे, जब मिलना-जुलना शुरू करेंगे तो आप लोगों को भी बुला लिया जाएगा। पर अभी भी गुत्थी सुलझ नहीं पा रही कि अचानक से भाजपा हाईकमान ने उन्हें बाहर का रास्ता क्यों दिखा दिया? उनसे जुड़े एक विश्वस्त सूत्र का दावा है कि धनखड़ पिछले दिनों (जब से विपक्ष ने खास कर कांग्रेस ने उन पर महाभियोग चलाने की धमकी दी थी) विपक्षी नेताओं से खूब मेल-जोल बढ़ाने में जुट गए थे। खास कर राहुल गांधी को लेकर उनका आग्रह भाजपा शीर्ष के गले नहीं उतर रहा था। वे टीएमसी नेताओं से मिल रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे-'मनी ड्रेन व ब्रेन ड्रेन तो रहा है, अगर अभी स्थितियां ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल कर बेहद मुश्किल होगी। सूत्रों का यह भी दावा है कि उन्होंने कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता को सलाह दी कि उन्हें चंद्रबाबू व एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं से बात करनी चाहिए।' कहते हैं धनखड़ के इन मनोभावों की जानकारी भाजपा की 'बी टीम' कहे जाने वाले दिल्ली के एक बड़े नेता ने भाजपा शीर्ष तक पहुंचा दी, इस नेता ने भाजपा शीर्ष से यह भी कह दिया कि 'धनखड़ विरोधी गुट के 300 सांसदों का एक धड़ा तैयार करने में मदद कर रहे हैं,' फिर क्या था गुस्से से लाल-पीला होते भाजपा शीर्ष ने धनखड़ की विदाई की पटकथा लिख दी।

बिहार एसआईआर आधार भी मान्य

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनाव लोकतांत्रिक चेतना का उत्सव होते हैं। चुनावी व्यवस्था की सफलता और विश्वसनीयता के पीछे सबसे बड़ा स्तम्भ भारतीय निर्वाचन आयोग है। चुनाव आयोग की भूमिका? निष्पक्ष पारदर्शी होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की विश्वसीयता उसकी संस्थाओं में जनविश्वास से तय होती है। भारत का लोकतंत्र केवल ईवीएम मशीनों से नहीं चलता। वह संस्थाओं की ईमानदारी और नागरिकों के विश्वास से चलता है। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर उठे विवाद के बाद चुनाव आयोग को विपक्षी दलों ने कठघरे में खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर पर अंतरिम आदेश दे दिया है, जिसमें चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि वह आधार कार्ड को मान्यता दे। शीर्ष अदालत ने हटाए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी अनुमति दी और कहा कि आधार कार्ड समेत फार्म-6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी एक जमा किया जा सकता है। पीठ ने चुनाव अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वह मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों के दावा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा कराने वाले राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंटों को पावती रसीद भी उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। विपक्ष ने दावा किया है कि सर्वोच्च अदालत के हस्तक्षेप से लोकतंत्र चुनाव आयोग के क्रूर हमले से बच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश यह भी दिया है कि उसने सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाते हुए उन मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया है जिनके नाम मतदाता सूची से कट गए हैं।

राजनीतिक दलों को फटकार लगाते हुए पीठ ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में जहां 1.68 लाख से ज्यादा बूथ स्तरीय एजेंट तैनात हैं, चुनाव आयोग के पास अब तक केवल दो आपत्तियां दर्ज कराई गईं। इतनी बड़ी संख्या में एजेंट होने के बावजूद इतना कम सहयोग गम्भीर सवाल खड़े करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को शामिल करके मतदाता सूची में संशोधन को अधिक समावेशी बनाने के लिए सुरक्षा उपाय किए हैं। इसकी सराहना की जानी चाहिए।

अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप तथ्यहीन शोर-शराबा है या संस्थागत दुर्भावना। बीते कुछ वर्षों में राजनीति का स्वरूप कुछ इस तरह का हो गया है कि चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना एक प्रचलन बन गया है। विपक्षी दलों को यह अधिकार है कि वह आलोचना करें, विरोध करें, सवाल उठाएं लेकिन साथ ही उन्हें संस्थाओं का सम्मान भी बनाए रखना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर में गड़बड़ियां हुई हैं। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने उन मतदाताओं को भी पेश किया है जिन्हें मतदाता सूची में मृत दिखाया गया है। एसआईआर में कई तरह की विसंगतियां हैं। कुछ मामलों में लोगों के पास दो-तीन और यहां तक कि चार एपिक मौजूद हैं। कुछ लोग एक ही बूथ पर कई बार रजिस्टर्ड हैं। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इन विसंगतियों को दूर करे। देश ने अपने चुनावी इतिहास में पिछले हफ्ते एक असाधारण स्थिति देखी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को कई मुद्दों पर चुनौती दी, जैसे कि डुप्लिकेट ईपीआईसी प्रविष्टियां, निर्वाचन क्षेत्रवार वृद्धि जो सांख्यिकीय रूप से अजीब लगती है,मशीन-पठनीय रोल देने से इन्कार और सीसीटीवी/वेबकास्ट फुटेज को 45 दिनों में हटाना आदि, जिससे चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब मताधिकार की अखंडता के बारे में विशिष्ट, जांच योग्य आरोपों का सामना करना पड़ता है तो क्या आयोग फाइल खोलता है या अपनी खेमेबंदी करता है? संस्था की ओर से •हलफनामा दायर करने• की पहली प्रतिक्रिया एक संवैधानिक प्रहरी के आत्मविश्वास से कम और एक प्रक्रियात्मक चाल ज्यादा लग रही थी। सवाल चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सशक्त भी बनाया है और सीमाओं में भी बांधा है। बिहार में एसआईआर ने आशंकाओं को जन्म इसलिए दिया है कि पहले की आधार रेखाओं की तुलना में मसौदा सूची से 65 लाख नाम गायब हैं। यद्यपि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह बिना सूचना सुनवाई और तर्कसंगत आदेश के किसी भी योग्य मतदाता को नहीं हटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड को मान्यता देने के बाद मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करना या भौतिक रूप से फार्म भरना आसान हो गया है।

चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट मिलकर मतदाता सूचियों की विसंगतियां दूर करें। लोकतंत्र की मजबूती मतदाता सूचियों के पवित्र होने पर ही निर्भर करती है।

"आवारा कुत्ते और सुप्रीम फैसला"

आवारा कुत्तों के मामले में देश की राजधानी दिल्ली समेत कितने ही महानगर समस्याएं झेल रहे हैं। कुत्तों के हमलों व बच्चों तथा बड़ों के काटे जाने की बढ़ती घटनाओं से क्षुब्ध होकर लोग छोटी अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कुछ दिन पहले सुप्रीम आर्डर जारी हुए कि दिल्ली सरकार व एमसीडी सड़कों पर आवारा कुत्तों को पकड़े, उन्हें शैल्टर घरों में रखे ताकि नागरिकों को राहत मिल सके लेकिन इस फैसले के खिलाफ डॉग लवर्स फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इस मामले में नए आर्डर दो दिन पहले जारी किए गए। जहां डॉग लवर्स संगठन खुश हैं वहीं आम जनता भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी हद तक संतुष्ट है। यहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देख लीजिए तो अच्छा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शैल्टर होम भेजे गए कुत्तों को स्टरलाइजेशन के बाद छोड़ने का आदेश दिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि वह पूरे देश के लिए एक समान नियम लागू करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि खतरनाक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कुत्तों को खाना देने के लिए एक निर्धारित स्थान बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर जगह कुत्तों को खाना देने से समस्या होती है। कोर्ट ने कहा कि हम इस फैसले को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि पशुपालन केंद्रों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और राज्यों के सचिवों को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने राज्यों के हाईकोर्ट में ऐसे ही लंबित मामलों को लेकर जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी मामले शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाएगा या पकड़ा गया है उनको नसबंदी और टीकाकरण कराने के बाद उसी इलाके में छोड़ा जाएगा। हालांकि कोर्ट का ये आदेश रेबीज से संक्रमित या आक्रमक कुत्तों पर लागू नहीं होगा लेकिन कोर्ट के पहले आदेश की तुलना में नया आदेश डॉग लवर्स के लिए एक बड़ी राहत की तरह जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश देते समय इसके साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। फैसले के अनुसार रेबीज से संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम को कुत्तों के लिए अलग फीडिंग प्वाइंट बनाने होंगे और सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाना मना रहेगा। यह आदेश पूरे देश में लागू होगा। हालांकि, डॉग लवर्स का कहना है कि अब भी उनकी दो बड़ी चिंताएं बरकरार हैं। पहली, आक्रामक कुत्तों की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। कौन सा कुत्ता आक्रामक है और कौन सा नहीं, इसका निर्णय कैसे होगा, यह सवाल सभी के मन में है। दूसरी, फीडिंग प्वाइंट से जुड़ी समस्या है। अदालत ने कहा है कि एमसीडी एक जगह खाना खिलाने के लिए जगह फिक्स करें, लेकिन हमारा मानना है कि इससे कुत्तों में लड़ाई हो सकती है और आम लोगों को भी इसकी सफाई की चिंता है, जो जायज है।

निर्णायक मोड़ : खनिज ईंधन से सस्ती हुई अक्षय ऊर्जा

प्रबीर पुरकायस्थ

नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा और खनिज ईंधनों के बीच मोड़ का बिंदु आ जाने पर एक नयी रिपोर्ट जारी करते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी चर्चा की कि कैसे हम अक्षय ऊर्जा के युग में प्रवेश कर रहे हैं और खनिज ईंधनों के अंत की शुरुआत हो गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इस रिपोर्ट के अनुसार,''2024 में बिजली उत्पादन क्षमताओं में सारे इजाफे में 92.5 फीसद हिस्सा और बिजली उत्पादन में कुल वृद्धि में 74 फीसद हिस्सा'', अक्षय ऊर्जा का था। जहां सारी दुनिया बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा की ओर मुड़ रही है, अमेरिका इकलौता 'विरोधी स्वर' बनकर सामने आता है, जिसका ट्रंप प्रशासन पर्यावरण में गिरावट से ही इंकार करता है और अब भी खनिज ईंधन का पक्ष ले रहा है। बेशक, वे इतिहास का मार्च रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन, इस तथ्य को देखते हुए कि इस मामले में समय पहले ही निकल चुका है, अमेरिका जो कि ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता है और दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है, गर्म दुनिया की ओर हमारे संक्रमण को बदतर तो बना ही सकता है। साथ में दिया गया चार्ट दिखाता है कि अक्षय ऊर्जा की लागतों में गिरावट के साथ, अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमताएं उल्लेखनीय तरीके से बढ़ी है और ऐसा खासतौर पर सोलर फोटोवोल्टिक संयंत्रों के मामले में हुआ है, जो सोलर पैनलों का उपयोग करते हैं। कन्सेंट्रेटेड सोलर प्लांट्स (सीएसपी) के मामले में, जो लेंसों/ दर्पणों का उपयोग कर, सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के जरिए, पानी को गर्म कर के भाप में तब्दील करते हैं और इस भाप का इस्तेमाल स्टीम टर्बाइन से संचालित परंपरागत बिजली जेनेरेटरों में किया जाता है, स्थिति अलग है। इस दशक के आखिर तक इन बाद वाले सोलर संयंत्रों से बिजली की लेवलाइज्ड लागत, खनिज ईंधन संयंत्रों के स्तर के करीब हो जाने की उम्मीद की जाती है। बहरहाल, भंडारण क्षमता वाले फोटोवोल्टिक संयंत्रों की कीमतों में भारी गिरावट हुई है और इसने सीएसपी संयंत्रों को आज कहीं ज्यादा महंगा विकल्प बना दिया है। शायद, रेगिस्तानी इलाकों में ये संयंत्र इस नियम के लिए अपवाद साबित हों। सीएसपी संयंत्रों का फायदा यह है कि उनके टर्बाइन अवत्वता मुहैया कराते हैं, जिससे ग्रिड को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। यह ऐसे ग्रिडों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिनके साथ अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या जुड़ी होती है। जैसा कि हमने पिछले ही दिनों, चंद महीने पहले हुए स्पेन में ग्रिड के बैठने के प्रकरण में देखा था, इस ग्रिड के बैठने का एक कारण ऐसे टर्बाइनों का अभाव था, जो पर्याप्त इनर्शियल इनर्शिया मुहैया करा पाते और इस तरह फ्रीक्वेंसी में उतार-चढ़ाव को संभालने की ग्रिड की क्षमता बढ़ पाते।

महत्वपूर्ण बदलाव

आइए, अपने ऊर्जा संक्रमण के सकारात्मक पहलू पर नजर डाली जाए। यह पहली बार है कि सौर तथा वायु ऊर्जा, कोयला, प्राकृतिक गैस या तेल से अब सस्ती हो चुकी है और नये बिजली उत्पादन के लिए यही सबसे तेजी से काम करने वाला विकल्प है। पिछले 3 से 5 वर्षों के दौरान खनिज ईंधन से अक्षय ऊर्जा की ओर इस संक्रमण में आए बदलावों को इस प्रकार देखा जा सकता है

* 2010-2022 के बीच सौर तथा पवन ऊर्जा, खनिज ईंधनों--कोयला तथा गैस--से, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्द्धी हुई है।

* 2023 तक, उपयोगिता पैमाने के सोलर फोटो वोल्टिक (पीवी) संयंत्र और तटीय पवन ऊर्जा की उत्पादन लागतें, खनिज ईंधनों के मुकाबले कम हो चुकी थीं।

* आज, नये पवन तथा सोलर पीवी संयंत्रों के करीब 75 फीसद से, खनिज ईंधन के चलने वाले पहले से वर्तमान संयंत्रों के मुकाबले सस्ती बिजली मिल रही है।

इस तरह, अक्षय ऊर्जा में जिस संक्रमण की बातें लंबे समय से की जा रही थीं, आ पहुंचा है! लेकिन, सवाल यह है कि क्या इसके लिए राजनीतिक इच्छा भी मौजूद है कि वह किया जाए जो न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से आवश्यक है बल्कि हम सब के लिए आर्थिक दृष्टि से भी एक बेहतर विकल्प है? या फिर पुरानी खनिज ईंधन लॉबी, खासतौर पर अमेरिका में यह लॉबी, एक कम कार्बन वाले भविष्य की ओर मानवता के संक्रमण को विफल कर देगी?

आइए, पहले तो उस बड़ी तस्वीर को देखें, जो पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आयी है। सौर तथा पवन ऊर्जा, अब ऊर्जा के सबसे से तेजी से बढ़ते स्रोत हो गए हैं और खनिज ईंधनों के मुकाबले कम लागतों पर बिजली मुहैया करा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह ऊर्जा, आर्थिक दृष्टि से कोयले और तेल के मुकाबले सस्ती होती जा रही है। बैटरियों की कीमतें घटने के साथ, ग्रिडों के स्थिर करने के लिए ग्रिड स्तर की बैटरियां लगाना तथा अल्पावधि जल-भंडारण व्यवस्थाएं जोड़ना भी, आर्थिक रूप से आकर्षक हो गया है।

दूसरे शब्दों में अगर अपने पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हम भूल भी जाएं तब भी, अक्षय ऊर्जा आज प्रतिस्पर्द्धी हो चुकी है। यही वह असली मोड़ है, जिसकी बात हम 1980 के दशक से करते आ रहे थे, जब पहली बार फोटोवोल्टिक उपकरण मंच पर आए थे। वह दिन आखिरकार आ पहुंचा है।

पर्यावरण की चिंता

यह हमें इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज या आईपीसीसी पर ले आता है। आईपीसीसी के दो लक्ष्य थे। एक लक्ष्य तो यह था कि सभी देशों को तेजी से पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए राजी किया जाए, जिससे वैश्विक ताप में सत्यानाशी बढ़ोतरी को रोका जा सके।

दूसरा लक्ष्य था, ऊर्जा संक्रमण पर खर्च करने के लिए, खासतौर पर कम आय वाले देशों को खनिज ईंधनों के उपयोग से उत्तरोत्तर दूर लाने के लिए, जरूरी संसाधन मुहैया कराना। इस तरह की पर्यावरणगत कार्रवाई को संचालित करने वाली समझ यह थी कि अमीर देश, जो अपने अतीत के कार्बन उत्सर्जनों के चलते मौजूदा कार्बन गुंजाइश का बड़ा हिस्सा पहले ही घेरे बैठे हैं, इस संक्रमण के लिए साधन मुहैया कराने में गरीब देशों की मदद करेंगे। ये दूसरे लक्ष्य किस हद तक पूरे हुए हैं? अमीर देश शुरुआत से ही पर्यावरणगत लक्ष्यों की बात करने के लिए तो तैयार रहे हैं, लेकिन अपने ऊर्जा संक्रमण के लिए गरीब देशों को फंड मुहैया कराने की बात करने के लिए तैयार नहीं रहे हैं। जहां यूरोपीय यूनियन और यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कार्बन गुंजाइश को घेरे हुए हैं, अपने अक्षय ऊर्जा संक्रमण में निवेश करने में लगे रहे हैं, वहीं अमेरिका ने न सिर्फ दो-दो बार वैश्विक पर्यावरणीय समझौतों से नाता तोड़ा है, उसने अपनी खनिज ईंधन कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिए हैं। राष्ट्रपति जार्ज बुश ने वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन समझौतों से यही कहते हुए नाता तोड़ा था कि अमेरिकी जीवन शैलियों पर, वैश्विक समझौता वार्ताएं मंजूर नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप उससे भी आगे बढ़ गए हैं। वह सिर्फ पर्यावरण परिवर्तन को नकारते ही नहीं हैं बल्कि खनिज ईंधन कंपनियों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं कि और ज्यादा कार्बन ईंधन जलाएं। और वह साइबेरिया तक में तेल तथा प्राकृतिक गैस के कुओं के लिए खुदाई करना चाहते हैं।

कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन कैप्चर का फर्जीवाड़ा

मैंने पहले भी इस संबंध में लिखा था कि आईपीसीसी द्वारा ''कार्बन क्रेडिट्स'' को अपनी चर्चा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाए जाने में क्या समस्याएं हैं? कार्बन क्रेडिट्स, सरल भाषा में कहें तो 'खून के बदले पैसा' या रक्त-धन का मामला है। अमीर देश, गरीब देशों को कार्बन सोख्ते बनाने या बनाए रखने के लिए पैसा देंगे, ताकि ये अमीर देश कार्बनयुक्त ईंधनों--कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस--का अपना अनाप-शनाप इस्तेमाल जारी रख सकें। जैसा कि हमने पहले ही विस्तार से बताया था, यह ज्यादातर हिसाब-किताब का फर्जीवाड़ा ही था, जिसमें कुछ खास कंपनियां फर्जी कार्बन क्रेडिट जारी करती थीं, जो अमीर देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन जारी रखने का मौका देता था। इस कार्बन रक्त-धन में से कुछ, विकासशील दुनिया में उनके कुछ साझेदारों तक भी पहुंचता होगा, लेकिन इस फर्जीवाड़े की ज्यादातर कमाई उन देशों में ही बनी रहती थी, जो इस तरह के कार्बन क्रेडिट जारी करते थे। अब जबकि अक्षय ऊर्जा की लागत घटकर कोयले से नीचे आ गयी है, उन कंपनियों का क्या होगा जो कार्बन कैप्चर का तमाशा कर रही थीं। ये कंपनियां कोई क्षतिपूरक वानिकी जैसी प्राकृतिक कार्बन सोख्तों के जरिए कार्बन कैप्चर की नहीं इस अर्थ में कार्बन कैप्चर की बात कर रही थीं कि खनिज ईंधनों को जलाने के बाद, धुएं की गैसों से कार्बन डाई आक्साइड को अलग किया जाए? यह एक और गाजर थी जो हमारे सामने लटकायी जा रही थी ताकि अमीर देश तेल, गैस, कोयला आदि को जलाते रह सकें। आज एक ही जगह में कार्बन कैप्चर की कोई आर्थिक प्रासंगिकता है और वह है कार्बन डाई आक्साइड का अलग किया जाना और इसका उपयोग, ''संवर्धित तेल निष्कर्षण परियोजना में किया जाना, जहां इसे आइल फील्ड्स में इंजैक्ट किया जाता है, जिससे उस अतिरिक्त तेल को निकाला जा सके, जो अन्यथा भूमि के भीतर ही फंसा रह गया होता।''(चार्ल्स हर्वी एंड कुर्ट हाउस, न्यूयार्क टाइम्स, 16 अगस्त 2022) इसीलिए, इन दोनों लेखकों ने कार्बन कैप्चर को 'बिग आइल्स लार्ज ग्रीन स्कैम' का नाम दिया है!

ग्रे हाइड्रोजन का मामला

खनिज ईंधनों का एक और उपयोग, उसके उत्पादन में है जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। इसमें इस्पात, अमोनिया, पेट्रोलियम शोधन, मेथनॉल तथा प्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बहरहाल, यह हाइड्रोजन वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है, जिसके लिए उसे ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। ग्रे हाइड्रोजन का उपयोग एक रसायन के रूप में किया जाता है, न कि एक ईंधन के रूप में। इस मामले में भी असली खिलाड़ी तेल कंपनियां ही हैं--एक्सोन, मोबिल, ब्रिटिश पैट्रोलियम (बीपी) और शैल। हैरानी की बात नहीं है कि इन तेल कंपनियों की कारोबारी गतिविधियों का विश्लेषण (ली एम ट्रेनर, जी एंड असुका जे, प्लोस वन, 16 फरवरी 2022) दिखाता है, ''खनिज ईंधनों पर बिजनस मॉडल की निर्भरता बनी हुई है...इस तरह हम यह नतीजा निकालते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा बिजनस मॉडलों की ओर संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि निवेशों का आकार और कदम, इसके विमर्श से मेल नहीं खाते हैं।'' दूसरे शब्दों में तेल कंपनियां, कार्बन कैप्चर, ग्रे हाइड्रोजन आदि के चोले में अपना, पहले की तरह ही काम चला रही है और इसके साथ ही बहुत सारी बातें बनायी जा रही हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने बन्ना ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पीरागढ़ी एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

हरगिज़ पड़ोसी भूखा ना सोने पाए- अल्लामा जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी

हजारीबाग़।

रविवार को अपने आवास रोमी चौक, हजारीबाग़ में प्रेस कर्मियों से बात करते हुए प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा जाबिर हुसैन सिद्दीक़ी ने फरमाया के- अरबी कैलेंडर के भी 12 महीने होते हैं।

मगर अरबी के तीसरे महीने को रबी उल अव्वल कहा जाता है। इस महीने की 12 तारीख़ को यह महानता हासिल है, कि अरब जगत के मक्का की पवित्र धरती पर 20 अप्रैल 571 ई को जगतगुरु हज़रत मोहम्मद का जन्म अब्दुल्लाह के घर में, आमना की गोद में हुआ। जो पूरे विश्व के लिए इंसानियत ,शांति और सद्भावना का उपदेश लेकर पूरी दुनिया से अपनी महानता और

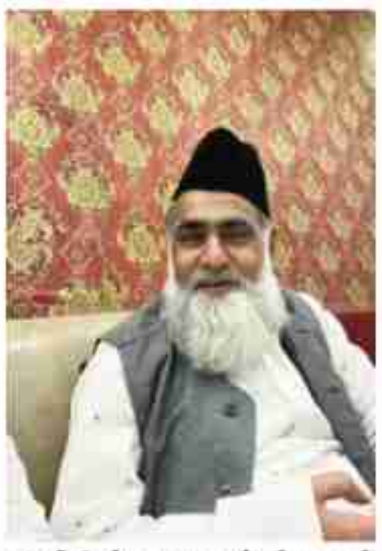

अपनी विशेषता मानवाते रहे। उनकी पूरी जीवनी ग़रीबों, बेवाओं, यतिमों, और लाचारों की सेवा में संपन्न हुई। उन्होंने यह फरमाया है की- मज़दूरों को उनका पसीना सूखने से पहले ही उनकी मज़दूरी दे दी जाए, ताकि, वह खुशी-खुशी अपने घर में अपने बच्चों के बीच चले जाएं, और उन्होंने यह भी फरमाया है कि- पड़ोसी अगर भूखा है, तो आपका पेट भर के खाकर सोना हराम है। इतना पड़ोसी का ख़्याल जगतगुरु ने फरमाया जितना किसी और धर्म में पड़ोसी को इतनी विशेषता नहीं प्राप्त है। आज अगर हम उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं और उनके उपदेशों पर अमल करना चाहते हैं, तो यही हमारा सबसे बड़ा ख़िराज ए अक़ीदत है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करके अपनी जिंदगी गुज़ारें और किसी को दुख ना पहुंचाएं। जिससे हमारी एकता और अखंडता बिगड़ने पाए। इसीलिए इनकी जीवनी पर एक करोड़ 86 लाख 522 किताबें और वार्ता लिखी गई हैं। जो उनकी महानता और उनकी विशेषता बताने के लिए काफ़ी है।

एक महीने से लापता विवाहिता मां और बेटा, पुलिस नहीं लगा पाई अभी तक पता

बहराइच। जिले के घुरघुट्टा निवासी आफरीन की शादी लखीमपुर खीरी थाना धौरारा लाला पुरवा के छोटू नामक युवक से डेढ़ वर्ष पहले हुई थी। बीते 17 जुलाई से आफरीन जिसकी गोद में आठ महीने का बच्चा भी है तभी से लापता है पर अभी तक लखीमपुर खीरी के थाना धौरारा की पुलिस न आफरीन का पता लगा पाई है न ही आठ महीने के बच्चे की वही लड़की के पिता का कहना है की हमारा दामाद छोटू अपने परिवार वालों के साथ मिलकर मेरी बेटी को मारता था और दहेज के लिए उत्पीड़न करता था और दहेज में मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग कर रहा था जिससे हम लोग गरीब होने के कारण देने से मना कर दिया तो मेरा दामाद मेरी लड़की आफरीन को अपने परिवार वालों के साथ मिलकर करने पीटने लगा जिससे मेरी लड़की आफरीन बीते एक महीने से लापता है जिसकी गोद में 8 महीने का बच्चा भी है जब इसकी जानकारी हमने लखीमपुर थाना धौरहरा प्रभारी को दिया तो वहां की पुलिस प्रार्थना पत्र लेने से मना करने लगी और पुलिस बोली जैसा हम लोग कहेंगे वैसे प्रार्थना पत्र लिखो और दो वही लड़की के पिता इकबाल का कहना है कि हमारे दामाद और उनके परिवार वालों ने मेरी लड़की फरीन को मार डाला है और लाश को कहीं छुपा दिया है या नदी में फेंक दिया है और मेरे दामाद ने वहां की पुलिस को पैसा दिया है जिससे हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है वही लड़की के पिता इकबाल जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है और कहां है की मेरी लड़की फरीन और 8 महीने का बच्चा को ढूंढने में हमारी मदद करे।

मूंढापांडे में रास्ते का रोड़ा हटाने पर हंगामा, पंचायत सदस्य और प्रधान आमने-सामने

मुरादाबाद। थाना मूंढापांडे क्षेत्र के ग्राम मूंढापांडे में रास्ते पर पड़े रोड़े को लेकर रविवार की सुबह जमकर बवाल हुआ। मामला इतना गरमा गया कि जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी और ग्राम प्रधान राघव कुमार आमने-सामने आ गए। राजस्व विभाग व पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से अवैध रोड़े हटाए गए। करीब तीन घंटे तक अफसरों और पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में तनाव का माहौल बना रहा।जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने न्यायालय आदेश की अवहेलना करते हुए कार्रवाई की है। वहीं ग्राम प्रधान राघव कुमार का कहना था कि खेल मैदान और निजी भूमि पर अवैध तरीके से रास्ता बनाया गया था, जिसे हटाया गया है। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाना मूंढापांडे में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है।

मै हुसैन से हूँ - मानवता' एवं सम्मान समारोह आयोजित

लखनऊ।

निराला सभागार, हिन्दी संस्थान में वन वाइस ट्रस्ट के तत्वावधन में इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि के रुप में सेमिनार व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था 'मै हुसैन से हूँ - मानवता' हूँ। सेमिनार के अतिथियों व वक्ताओं में जज श्री शमीम आबिद, सचिव वित्त विभाग श्री शाहिद मन्ज़र रिज़वी, इरा वि0वि0 के वीसी प्रो0 अब्बास अली मेंहदी, डा0 असद अब्बास, प्रो0 रविकान्त, सुनिता झिंगरन, डा0 राजकमल यादव, नजमुल हसन 'नजमी', व श्री अश्वनी शर्मा शामिल थे, जिन्होंने इमाम हुसैन को इन्सानियत का पर्यावाची बताया, और कहाँ मानवता को अगर सही ऊचाँई मिली है, तो वह करबला की घटना के बाद जहां इन्सानियत के लिए इमाम ने अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दे दी।

'निशान-ए-इमाम हुसैन' सम्मान

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े तीन विभूतियों व तीन संस्थानों को, जिन्होंने इमाम हुसैन अ.स. के पैग़ाम को आगे बढ़ाया या आगे बढ़ाने में सहयोग किया, उनको 'निशान-ए-इमाम हुसैन' सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें रेशमा जलाल, एडवोकेट मीसम ज़ैदी, सहर उर्दू टीवी ईरान, सै0 ज़फर रज़ा, राज्य ललित कला अकादमी उ0प्र0, व तन्ज़ीमें वहदत अन्जुमने मोहब्बते अहलेबैत।

'पैग़ामें-ए-इमाम हुसैन' सम्मान

17 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मोहर्रम प्रदशर्नी को पूर्ण सहयोग करने वालों को 'पैग़ामें-ए-इमाम हुसैन' सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें मुसददीक़ रज़ा कुम्मी, तबस्सुम फातमा, डा0 सरवत तक़ी, मज़ाहिर रज़ा, मो0 मोहसिन रिज़वी व वली हसन रिज़वी शामिल थे। पेन्टिंग 17 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मोहर्रम प्रदशर्नी में प्रथम पुरस्कार इरतिक़ा ज़ैदी- बहराइच व बरीज़ा नाज़िम, द्वितीय पुरस्कार सायमा अख़्तर - शाहजहापुर, तृतीय पुरस्कार लाइबा मिर्ज़ा, संतावना पुरस्कार लुबना, मरियम मुर्तज़ा व हाजी महताब वारसी, देहरादून।

फोटोग्राफी 17 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मोहर्रम प्रदशर्नी में

प्रथम पुरस्कार हिकमत अलैशी- इराक़, द्वितीय पुरस्कार शमशेर वारसी -देहरादून, तृतीय पुरस्कार मोहसीन करम अली, संतावना पुरस्कार मुश्ताक़ अली व अंकित सिंह।

कैरीग्राफी 17 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय मोहर्रम प्रदशर्नी में प्रथम पुरस्कार साहिबा सुल्ताना, द्वितीय पुरस्कार नाइशा हसन, तृतीय पुरस्कार मुमताज़ जहां, संतावना पुरस्कार फौज़िया खातून, निख़त फातमा व फाक़ेहा, स्पेशल पुरस्कार फ़ाकिया अहसन। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के सचिव एस.एन.लाल ने किया अन्य अतिथियों में डा0 मसीहउद्दीन ख़ान, इसरार, कुलसुम तलहा, नवाब मसूद अब्दुल्लाह, मेराज हैदर, प्रो0 साबिरा हबीब व रौशन तकी उपस्थित थे।

वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन सम्पन्न

कानपुर।

वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक भागीदारी महासम्मेलन आज शहनाई गेस्ट हाउस, भन्नानापुरवा, कानपुर में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस महासम्मेलन का आयोजन वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविशंकर हवेलकर के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 2 बजे भाजपा कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल सांसद रमेश अवस्थी अवस्थी,विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर रविशंकर हवेलकर ने महासम्मेलन में वंचित समाज की 11 प्रमुख मांगें केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष रखी। इनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का शीघ्र गठन, रिक्त पड़े लाखों सफाई कर्मियों के पदों पर सीधी भर्ती, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना, अनुसूचित जातियों की छात्रवृत्ति योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करना, आउटसोर्सिंग एवं ठेका प्रथा

में कार्यरत सफाई कर्मियों का न्यूनतम सम्मानजनक वेतन 25,000 किया जाना, सफाई कर्मचारी कॉलोनियों को मालिकाना हक प्रदान करना, शहीद क्रांतिकारी गंगू बाबा वाल्मीकि की प्रतिमा को बिठूर स्थित नाना राव पर्यटन स्थल पर स्थापित करना, बसोर समाज के महापुरुष गुरुकुल गोकुलदास महाराज की जन्मस्थली (ग्राम जयपुर बेलाताल, जिला महोबा) पर समाधि स्थल का जीर्णोद्धार एवं स्मारक के रूप में विकसित करना, सहित अन्य मांगें शामिल थीं।

सम्मेलन में देश-विदेश से आए वंचित वर्गों के प्रतिनिधियों ने संविधान की परिकल्पना, वंचित समाज की दशा-दिशा, उनकी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति पर व्यापक चर्चा की। केंद्र एवं राज्य सरकार से वाल्मीकि, बसोर, धरकार, वंशकार, बरार आदि जातियों को शून्य प्रतिशत हिस्सेदारी मिलने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई।

सांसद रमेश अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा -

मैं बाल्मिक समाज के एक मेधावी छात्र को निःशुल्क आईएएस कोचिंग की व्यवस्था करूंगा।

इसके अतिरिक्त बाल्मिक समाज के बच्चों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कानपुर में विशेष व्यवस्था की जाएगी। क्रांतिकारी गंगू बाल्मीकि की विशाल प्रतिमा चुन्नी गंज चौराहे पर लगेगी।

भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा-

भगवान महर्षि वाल्मीकि ने प्रभु श्रीराम के नाम को जन-जन तक पहुंचाया। मुगलों के समय जब धर्मांतरण नहीं किया गया, तब मैला उठाने की परंपरा जबरन थोपी गई। मुझे गर्व है कि इस समाज ने इस्लाम नहीं अपनाया, अपितु संघर्ष किया और अपनी पहचान बनाए रखी। अब समय है कि बाल्मिक समाज शिक्षित होकर प्रगति करे।

विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद (निर्मल) ने कहा -

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाल्मिक समाज का सम्मान किया है। कांग्रेस और सपा ने सदैव हमारे समाज को भ्रमित किया। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल संविधान निर्माता का सम्मान किया, बल्कि पूरे वंचित समाज का गौरव बढ़ाया है। महासम्मेलन को के.डी. राही, बिंदा प्रसाद मोदिया, अजय पत्रकार, देव कुमार, सुशील शेरवा, अनूप बाल्मिकी, ब्रजेश कुमार, प्रीति सोनकर सहित कई सामाजिक प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर वंचित समाज की सामाजिक-राजनीतिक मजबूती का संकल्प लिया ।

बिना अनुमति हो रहा था मस्जिद का निर्माण, विरोध के बाद पुलिस ने तुड़वाया

ठाकुरद्वारा। बिना अनुमति रातों-रात कोतवाली क्षेत्र के गांव निर्मलपुर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद के लिए चारदीवारी बनानी शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देख मजदूर फरार हो गए। मुस्लिम समुदायों की महिलाओं ने निर्माण को तोड़े जाने पर विरोध किया। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह ग्वाल भारी पुलिस बल लेकर पहुंचे। विरोध कर रही महिलाओं को समझाया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि बिना अनुमति कोई भी धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाना गैर कानूनी है। जिसके बाद महिलाएं लौट गई। रविवार सुबह 11:00 बजे सूचना मिली कि मुस्लिम समुदाय के लोग रातों-रात सरकारी भूमि पर मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं । पुलिस बल को मौके पर पहुंचते ही निर्माण करने वाले पर मजदूर फरार हो गए । पुलिस को देख मुस्लिम वर्ग की महिलाओं ने निर्माण गिराने का विरोध शुरू दिया । हिंदू समुदाय के लोगों ने बताया कि 2014 में भी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने बिना अनुमति उक्त भूमि पर मस्जिद का निर्माण शुरू किया था जिस पर दोनों पक्ष के लोगों में तनातनी हो गई थी। जिस पर पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत करते हुए निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस ने चारदीवारी तुड़वा कर उस पर रोक लगा दी । चेतावनी दी कि यदि भविष्य में इस तरह का कार्य करने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी । कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जसपाल सिंह ग्वाल ने बताया कि वर्ष 2014 में भी अनुमति के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मस्जिद का निर्माण शुरू किया था उसे समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी जिस पर प्रशासन ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों के प्रति गंभीर नहीं दिल्ली पुलिस, अफसरों की लापरवाही पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली। नाबालिग से दुष्कर्म जैसे संगीन मामले की जांच के प्रति दिल्ली पुलिस की गंभीरता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के पेश न होने से लेकर पूरे मामले के संबंध में लोक अभियोजक को जानकारी नहीं देने पर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि अभियोजक व जांचकर्ता जमानत याचिका का विरोध नहीं करना चाहते है। हालांकि, न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आरोपित को जमानत दी जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता ने ट्रायल में अपनी गवाही के दौरान दुष्कर्म होने का बयान देकर अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया। ऐसे में अदालत आरोपित की जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं है और जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) नोटिस स्वीकार करते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया था।

हालांकि, अदालत ने यह भी नोट किया कि एपीपी अदालत के समक्ष मामले में जिरह नहीं कर सके क्योंकि दिल्ली पुलिस के संबंधित जांच अधिकारी मामले से जुड़ी जांच व पुलिस फाइल नहीं लाए थे, जबकि एसएचओ इंस्पेक्टर मनीष भट्टी को मामले में हुई प्रगति की जानकारी नहीं थी। एपीपी ने पीठ को सूचित किया था कि इंस्पेक्टर मनीष भट्टी एसएचओ नहीं बल्कि एटीओ है और पहले उन्होंने इंस्पेक्टर को एसएचओ समझ लिया था। उक्त तथ्यों को रिकॉर्ड करते हुए पीठ ने कहा कि पूर्व में कई बार निर्देश दिया जा चुका है कि संगीन अपराध के मामलों में जांच अधिकारियों को सुनवाई शुरू होने से पहले अभियोजक को जानकारी देनी चाहिए और सुनवाई के दौरान फाइल के साथ अदालत में उपस्थित रहना चाहिए। पीठ ने कहा कि व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए ऐसे आदेशों की प्रतियां बार-बार संबंधित पुलिस उपायुक्तों को भेजी गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में भी जांच अधिकारियों की विफलता के कारण एपीपी अदालत के समक्ष तथ्यों को पेश नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति इस तरह का उदासीन रवैया स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ता को अदालत के समक्ष गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए आवश्यक रिकार्ड पेश किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसा नहीं हो रहा है। पीठ ने उक्त स्थिति को देखते हुए आदेश की प्रति मामले की जांच के लिए पुलिस आयुक्त को भेजने का निर्देश दिया। याचिका के अनुसार आरोपित ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में भलस्वा डेरी थाना में दर्ज प्रकरण में नियमित जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार अगस्त 2024 में आरोपित ने मोहल्ले में खेल रही 13 वर्षीय किशोरी को किसी काम के बहाने बुलाया और उसे अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के कारण किशोरी गर्भवती हो गई थी। आरोपित ने जमानत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि मामले में सभी गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और वह नवंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में जेल में है। उसने रिहा करने की मांग करते हुए यह भी तर्क दिया कि उसे सुधार करने का एक मौका दिया जाना चाहिए।

पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का एनकाउंटर

पुलिस ने कहा- मेडिकल कराने के दौरान भागने की कोशिश की, पैर में गोली लगी

ग्रेटर नोएडा।

ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर पति और ससुरालवालों द्वारा की गई महिला की हत्या मामले में पति विपिन ने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा और मुझे कोई पछतावा नहीं है. बता दें कि गुरुवार देर रात को विपिन और उसकी मां ने मिलकर निक्की को आग के हवाले करते हुए मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया था.

मेरी पत्नी चली गई... हां बहुत पछतावा है- विपिन

इसी बीच जब पुलिस रविवार को विपिन को सबूत जुटाने के लिए घर लेकर गई थी तो उसने भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से एनकाउंटर में उसके पैर पर गोली लग गई थी. इसके बाद जब पुलिस विपिन को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद एनडीटीवी संवाददाता ने आरोपी विपिन से कुछ सवाल किए. इस दौरान उसने कहा कि मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैंने उसे नहीं मारा. हर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते है वह खुद मरी है. इसके तुरंत बाद ही जब विपिन से एक बार फिर पूछा गया कि क्या आपको कोई पछतावा है तो उसने कहा कि, हां मुझे बहुत पछतावा है... मेरी पत्नी चली गई.

दहेज मांगने का लगाया आरोप

निक्की के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि निक्की का पति और उसके ससुराल के लोग दहेज देने के बाद भी बार-बार और पैसों की मांग करते रहते थे. यहां आपको बता दें कि निक्की को उसके बेटे के सामने ही पति और सास ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी. इस बारे में जब अधिकारियों ने निक्की के बेटे से सवाल किया था तो उसने कहा था, मेरे पापा ने मेरी मां को मार दिया.

निक्की की बहन ने भी लगाया मारपीट का आरोप

यहां आपको यह भी बता दें कि निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी घर में हुई है. कंचन की शादी विपिन के भाई के साथ हुई है और कंचन ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी मारपीट की जाती थी और वो अपनी बहन की जान नहीं बचा पाई. जिस रात निक्की के साथ मारपीट कर उसे आग के हवाले किया गया था, उसी रात कंचन के साथ भी मारपीट की गई थी और फिर वह बेहोश हो गई थी.

बहन कंचन ने कही ये बात

कंचन ने भी आरोप लगाया है कि उसके और निक्की के बेटे के सामने उसे विपिन और ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी.

लोग हमें वोट डालते और चला कहीं और जाता- राज ठाकरे

मुंबई। बिहार चुनाव से पहले वोटी चोरी और फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा छाया हुआ है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि पिछले 10 वर्षों से वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी।

वोट चोरी के मुद्दे पर मैंने विपक्षी नेताओं से बात की- राज ठाकरे

राज ठाकरे ने कहा कि वोट चोरी पिछले 10 वर्षों से हो रही है और उन्होंने 2016 से इस मुद्दे पर बात की है। उन्होंने शरद पवार, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात की है। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग को इस मामले की जांच करनी चाहिए थी, लेकिन वह जानबूझकर मामले को दबा रहा है क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 वर्षों की वोट चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा।

हमारे उम्मीदवार के वोट कहीं और चले गए : राज ठाकरे

राज ठाकरे ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची की सावधानीपूर्वक जांच करने का आग्रह किया ताकि वोट चोरी का पर्दाफाश किया जा सके। बता दें कि साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव मे एमएनएस एक भी सीट जीतने में असफल रही। ठाकरे ने कहा कि उनके उम्मीदवार इसलिए हार गए क्योंकि उनके लिए डले गए वोट कभी उनके पास नहीं पहुंचे।

जस्टिस जेबी पारदीवाला के आदेशों से सुप्रीम कोर्ट में उलझन, चीफ जस्टिस को करना पड़ा हस्तक्षेप

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस जेबी पारदीवाला के हाल के आदेशों ने शीर्ष अदालत को उलझन में डाल दिया है। पिछले एक महीने के भीतर उनकी अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से दिए गए तीन बड़े आदेशों पर इतना विवाद हुआ कि अंततः मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई को दखल देना पड़ा। पहला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ा था। जस्टिस पारदीवाला ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज प्रशांत कुमार की सख्त आलोचना की थी। उनका कहना था कि प्रशांत कुमार ने एक सिविल विवाद में आपराधिक कार्यवाही की अनुमति देकर गंभीर गलती की है। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि अब से प्रशांत कुमार को उनकी रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस न दिया जाए।

पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही भाजपाः अखिलेश यादव

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधायक पूजा पाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। पूजा पाल को बताना चाहिए कि उन्हें किससे जान का खतरा है? अभी उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव उन आरोपों पर बयान दे रहे थे जिसमें विधायक पूजा पाल ने कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सपा और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग फ्रस्टेट हो गए है इसीलिए अमर्यादित हरकतें कर रहे है। अभी बलिया में बिजली विभाग के कार्यालय में घुसकर एक दलित समाज से आने वाले इंजीनियर को जूतों से पीटा। उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्पष्ट दिखाई दे रहे है। कुछ समय बाद इनके नेताओं के हाथों में जूता ही नजर आएगा।

वोटर अधिकार यात्रा में जाएंगे

सवाल पूछे जाने पर कि क्या वो बिहार में हो रही वोटर अधिकार यात्रा में जाएंगे? इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये यात्रा इंडिया गठबंधन की है। हम इसमें जरूर जाएंगे। जल्द ही कार्यक्रम जारी हो जाएगा।

सपा प्रदेश अध्यक्ष ने गृहमंत्री को लिखा पत्र

सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने विधायक पूजा पाल के जान का खतरा होने के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है कि मामले की पूरी जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि सपा ने पूजा पाल का मुश्किल समय में साथ दिया था। ऐसे में उन्हें किससे जान का खतरा है इसकी जांच करवाई जाए।

कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए..., सीएम योगी ने दिए निर्देश

गोरखपुर।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने ध्यान से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का निस्तारण तत्परता और संवेदनशीलता से किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''समस्याओं के निस्तारण में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में आए लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिले और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं।

सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी

सीएम योगी ने करीब 200 लोगों से मुलाकात की और सभी को आश्वस्त किया कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले या कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर भी आए थे। मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी।

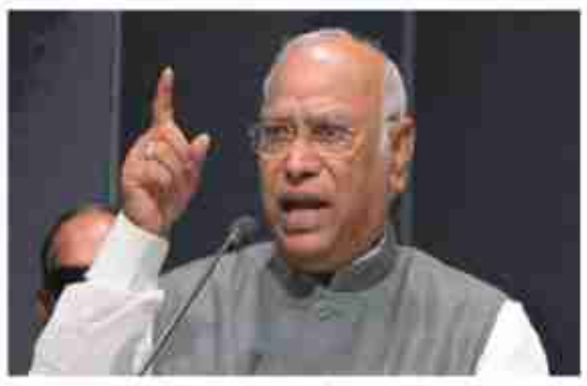

मल्लिकार्जुन खरगे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा- वोट चोरी के बाद सत्ता चोरी में जुटी भाजपा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी के बाद भाजपा अब सत्ता चोरी में लगी हुई है। भाजपा 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने और गिरफ्तारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर लोकतंत्र को अस्थिर करने के लिए विधेयक ला रही है। इंदिरा भवन में हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिला कांग्रेस समितियों के जिलाध्यक्षों की बैठक में खरगे ने दावा किया कि ये विधेयक नागरिकों से उनकी चुनी हुई सरकार बनाने या हटाने का अधिकार छीन लेते हैं और यह शक्ति ईडी-सीबीआई जैसी संस्थाओं को दे देते हैं। यह लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है।

बूथ और मंडल समितियों के गठन में सावधानी बरतें जिलाध्यक्ष

खरगे ने जिला कांग्रेस प्रमुखों को बूथ और मंडल समितियों के गठन में विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इन समितियों के लोग पार्टी के प्रति वफादार हों और कांग्रेस की विचारधारा से विचलित न हों। जिला अध्यक्ष अपने अधीन ब्लॉक समिति बनाता है। वह मंडल और बूथ समितियां बनाता है। जब आप ये समितियां बनाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये सभी लोग पार्टी के प्रति वफादार और मेहनती हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कांग्रेस की विचारधारा से विमुख न हों। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है कि अगर कोई उन्हें प्रलोभन भी दे तो भी उनकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने मजबूत संगठन के कारण लंबे समय तक देश पर शासन किया और मंत्रियों के लिए यह जरूरी है कि वे जब भी किसी जिले में जाएं तो सबसे पहले जिला अध्यक्ष से संपर्क करें।

कांग्रेस की सबसे मजबूत कड़ी हैं जिला प्रमुख

उन्होंने हरियाणा और मध्य प्रदेश के जिलाध्यक्षों से कहा कि वे कांग्रेस संगठन की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर राज्य में सरकार बनानी है तो विधानसभा में उम्मीदवार को जिताने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर देश में सरकार बनानी है तो लोकसभा जीतने के लिए आपके समर्थन की जरूरत है। बीच में इस परंपरा में थोड़ा बदलाव आया। मंत्री अपने पसंदीदा लोगों को जिला अध्यक्ष बनाने लगे। योग्यता और विचारधारा को नजरअंदाज किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मुझे यह अहसास हुआ कि संगठन को मजबूत किए बिना, जिला अध्यक्षों को महत्व दिए बिना हम मजबूती से सत्ता में वापसी नहीं कर सकते। कांग्रेस प्रमुख ने जिला प्रमुखों से गुटबाजी से बचने और संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह किया। आपको सभी को एकजुट रखना होगा। गुटबाजी को पनपने न दें। जब कांग्रेस एकजुट रहेगी, तभी हम चुनाव जीतेंगे।

मतदाता सूची का निरीक्षण करते रहें

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी थी कि किस तरह कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर एक साजिश के तहत रणनीतिक तरीके से वोट चुराए गए। हमें यह सब छह महीने के शोध के बाद पता चला। चुनाव आयोग ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। अब पूरा देश इसे समझ रहा है। बिहार में एसआईआर पर भाजपा सरकार और चुनाव आयोग के बयान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मानसून सत्र को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विपक्ष चाहता था कि संसद चले और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चाहती थी कि एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) और वोट चोरी जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो। भाजपा एसआईआर जैसी योजनाओं से हमारे लोगों के वोट काटती रहेगी। जिला अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमें पूरे पांच साल सावधान रहना है। हमें अपनी मतदाता सूची की गहन जांच करते रहना होगा ताकि अगर भाजपा के लोग या बीएलओ हमारे लोगों के नाम काटते हैं, तो हम उन्हें तुरंत पकड़ सकें। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि कि वे लोगों को बताएं कि इस देश में सभी को वोट देने का अधिकार कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी ने ही मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी ताकि लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। राहुल गांधी की बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं।

केवल दो नेताओं के खिलाफ ही हुए दोष सिद्ध

हमने देखा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ 193 मामलों में से ईडी की कार्रवाई से केवल दो मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है। कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और महीनों तक जेल में रखा गया। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के बारे में बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उन सभी लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया है, जिन्हें वे भ्रष्ट कहते थे और यहां तक कि उन्हें मंत्री भी बना दिया है।

जब भी सदन की गरिमा से समझौता हुआ, इसके भयंकर परिणाम देखने पड़े, सभापति सम्मेलन में बोले शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद या विधानसभाएं बहस और चर्चा की जगह हैं, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए सदन को चलने न देना ठीक नहीं है। शाह ने अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। संसद का मानसून सत्र विपक्ष के विरोध के चलते बार-बार बाधित हुआ और सत्र के दौरान काफी कम काम हुआ। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि जब संसद में सीमित बहस या चर्चा होती है, तो इससे राष्ट्र निर्माण में सदन का योगदान प्रभावित होता है।

संकीर्ण राजनीतिक फायदे के लिए सदन न चलने देना ठीक नहीं

अमित शाह ने कहा लोकतंत्र में बहस होनी ही चाहिए। लेकिन किसी के संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए, विपक्ष के नाम पर सदन को चलने न देना ठीक नहीं है। विपक्ष को हमेशा संयमित रहना चाहिए। देश को इस पर विचार करना होगा, जनता को इस पर विचार करना होगा और निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस पर विचार करना होगा। शाह ने कहा कि सभी चर्चाओं में सार्थकता होनी चाहिए और सभी को अध्यक्ष पद की गरिमा और सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हमें जनता के मुद्दों को उठाने के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने के लिए काम करना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन का संचालन नियमों के अनुसार हो। हस्तिनापुर में द्रौपदी के अपमान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब भी सदन की गरिमा से समझौता हुआ है, देश को इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले है।

गृह मंत्री ने विठ्ठलभाई पटेल को किया याद

गृह मंत्री ने आजादी के बाद से भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की सराहना की और कहा कि यहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सत्ता परिवर्तन के दौरान खून की एक बूंद भी नहीं गिरी है, जबकि कई देशों में लोकतांत्रिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। शाह ने संसद के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले आज ही के दिन, महान स्वतंत्रता सेनानी विठ्ठलभाई पटेल को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिससे भारत के विधायी इतिहास की शुरुआत हुई। शाह ने कहा कि अगर देश को आजादी दिलाना अहम था तो लोकतंत्र की स्थापना और विधायी प्रक्रियाओं की स्थापना भी उतनी ही महत्वपूर्ण काम है। विठ्ठलभाई पटेल ने कठिन समय में भी लोकतंत्र की स्थापना और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सभी को यह बात याद रखनी चाहिए।

चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है - राहुल-तेजस्वी

अररिया।

बिहार के अररिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देशभर में वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है. वहीं, तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है.

राहुल गांधी बोले- वोट चोरी हो रही है

राहुल गांधी ने कहा कि अब करोड़ों लोग मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी को वोटर लिस्ट तक नहीं दी गई. राहुल ने कहा- हमने कर्नाटक में दिखाया कि कैसे वोट की चोरी हुई. बिहार में ऐसा नहीं होने देंगे. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी यात्रा के दौरान छोटे-छोटे बच्चे आकर कह रहे है - वोट चोर गद्दी छोड़. राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग अगर इन बच्चों से बात कर ले, तो सच्चाई खुद पता चल जाएगी.

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से किए सवाल

राहुल गांधी ने कहा- मैंने कर्नाटक के महादेवपुरा से जुड़ा डेटा रखा और चुनाव आयोग से पूछा कि 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? चुनाव आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया. मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा. कुछ दिन बाद बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट नहीं मांगा. मैंने फर्जी वोटर की बात की, अनुराग ठाकुर ने भी वही बात दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग का उनसे एफिडेविट न मांगना दिखाता है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है. एसआईआर संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका है. बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और बीजेपी के बीच पार्टनरशिप है.

तेजस्वी यादव का हमला - चुनाव आयोग बना बीजेपी का कार्यकर्ता

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा - अब चुनाव आयोग गोदी आयोग हो गया है. वह बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है. जमीनी स्तर पर हम घूमे हैं और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह खत्म हो गई है. तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा - इतना झूठा पीएम हमने आज तक नहीं देखा. अफवाह फैलाना इनका काम है. जब बिहार आए तो घुसपैठियों का जिक्र किया, लेकिन चुनाव आयोग के एफिडेविट में एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं है.

मुकेश सहनी का बयान -वोट ही सबसे बड़ी ताकत

VIP पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वह पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे है. उन्होंने कहा - वोट ही सबसे बड़ी ताकत है. जब तक वोट का अधिकार रहेगा, समाज में हमें बराबर समझा जाएगा.

दीपांकर भट्टाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिया हवाला

भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यह साफ हो गया कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर डाल रहा है.